Limited proposes to set up a 6 MMTPA grass-root refinery at Deogarh (Maharashtra) at an estimated cost of Rs. 4407 crores as a joint venture with M/s Oman Oil Company Limited. First Stage clearance has been accorded to the project by the Government. The proposal is now under process for investment decision.

Mobile Post Offices in U.P.

*693. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what is the number of villages, district-wise, in Uttar Pradesh with a population of 500-1000 which do not have post offices;

(b) what is the present criterion for opening post offices in rural areas;

(c) what is the number of villages in U.P. where post is not delivered on a daily basis and by when such facilities are proposed to be extended to all the villages; and

(d) what is the position of mobile post offices in U.P., the district-wise number of villages covered and what are the plans for extension of mobile post offices in U.P. in the current Plan?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) The number of villages district-wise, in Uttar Pradesh with a population of 500-1000 which do not have Post Offices is given in statement (*see* below).

(b) The present criterion for opening of Post Offices in Rural areas is given in Statement-II (*see* below).

(c) There is daily delivery of mail in all the villages in Uttar Pradesh.

(d) Mobile Post Office services in rural areas of U.P. do not exist. There is no plan to introduce mobile post office service in UP or elsewhere at present. However, more Gram Panchayat villages are likely to be covered with Post Office facility on introduction of Panchayat Sanchar Sewa Scheme.

Statement-I

Number of villages district-wise in Uttar Pradesh with a population of 500-1000 which do not have Post Offices

Sl. No.	Name of district	Villages with a population of 500-1000 without post offices
1.	Allahabad	989
2.	Almora	184
3.	Azamgarh	965
4.	Agra	204
5.	Aligarh	470
6.	Banda	283
7.	Barielly	579
8.	Budaun	576
9.	Barabanki	589
10.	Basti	1132
11.	Ballia	400
12.	Bahraich	450
13.	Bulandsahar	290
14.	Bijnor	569
15.	Chamoli	70
16.	Deoria	1039
17.	Dehradun	68
18.	Etah	429
19.	Etawah	394
20.	Fatehpur	379
21.	Farukhabad	445
22.	Faizabad	658
23.	Firozabad	236
24.	Ghazipur	590
25.	Ghaziabad	99
26.	Gorakhpur	748
27.	Gonda	749
28.	Hardoi	524
29.	Haridwar	105
30.	Hamirpur	213
31.	Jaunpur	822
32.	Jhansi	217
33.	Jalaun	270
34.	Kanpur city	60
35.	Kanpur Dehat	513
36.	Kheri	431
37.	Lucknow	267

1	2	3
38.	Lalitpur	204
39.	Moradabad	735
40.	Mirzapur	439
41.	Mau	314
42.	Maharajganj	307
43.	Mathura	170
44.	Mainpuri	254
45.	Meerut	114
46.	Muzaffarnagar	99
47.	Nainital	271
48.	Pilibhit	339
49.	Pithoragarh	89
50.	Pratapgarh	606
51.	Pauri Garhwal	63
52.	Rampur	334
53.	Raibareli	476
54.	Sonabhadra	249
55.	Sitapur	652
56.	Sultanpur	652
57.	Sidharthnagar	738
58.	Saharanpur	670
59.	Shahjahanpur	606
60.	Tehri Garhwal	170
61.	Uttarkashi	49
62.	Unnao	547
63.	Varanasi	938
	TOTAL:	26758

Statement-II

Norms for opening of Post Offices

1. *Norms for opening of new Branch Post Office*

1.1 *Population:*

(a) *In Normal Areas:*

300 population in a group of villages (including the PPO Villages)

(b) In the Hilly, Tribal, Desert and Inaccessible Areas:

500 population in an individual village or 1000 population in a group of villages

1.2 *Distance:*

(a) *In Normal Areas:*

The minimum distance from the nearest existing Post Office will be 3 Kms.

(b) *In Hilly, Tribal, Desert and Inaccessible Areas:*

The distance limit will be the same as above except that in Hilly Areas, the minimum distance limit can be relaxed by the Directorate in cases where such relaxation if warranted by special circumstances which should be clearly explained while submitting a proposal.

1.3 *Anticipated Income:*

(a) *In Normal Areas:*

The minimum anticipated revenue will be 33 1/3% of cost.

(b) *In Hilly, Tribal, Desert and Inaccessible Areas:*

The minimum anticipated income will be 15% of the cost.

2. *Norms of opening new Departmental Sub-Post Office.*

2.1 The minimum of work load of the Extra Departmental Branch P.O. Office should be five hours per day.

2.2 The permissible annual loss should be not more than Rs. 2400/- in normal rural areas and Rs. 4800/- in Tribal and Hilly area. However, in Urban areas, the Post Office should be initially self supporting and at the time of the first annual review it should show 5% profit to be eligible for further retention.

2.3 The minimum distance between two post office should be 1.5 Km. in cities with a population of 20 lakhs and above, and 2 kms in other urban areas. No two delivery offices, however, should be closer than 5 Kms. for each other.

Heads of Circles have powers to relax the distance condition in 10% of the cases.

2.4 A Delivery Post Office in Urban Area should have a minimum of 7 Postmen's beats.

मध्य प्रदेश में जंगली हाथियों के आतंक को रोकने के लिए किया गया व्यय

*694. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 1988-89 से 1994-95 तक जंगली हाथियों के आतंक को रोकने के लिए वर्ष वार कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) जंगली हाथियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा कितने परिवारों को किस दर से क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान जंगली हाथियों को पकड़ने और उन्हें पालतू बनाने पर कितनी राशि खर्च की गई तथा इन हाथियों के पकड़े जाने के पश्चात उनकी देखभाल तथा खान-पान पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) मध्य प्रदेश को जंगली हाथियों के आतंक से मुक्त कराने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हाथी परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मंजूर निम्नलिखित राशि खर्च करके मध्यप्रदेश राज्य में जंगली हाथियों की समस्या से निपटा गया:-

1988-89 से 1992-93	शून्य
1993-94	17.924 लाख रुपए
1994-95	34.15 लाख रुपए

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1988-89 तथा 1993-94 के बीच, इस समस्या से सफलतापूर्वक निपटने से पहले 42 व्यक्ति मारे गए थे, फसल और सम्पत्ति को हुई क्षति के 6516 मामले सूचित किए गए थे तथा मुआवजे के रूप में 64.42 लाख (लगभग) रुपए की राशि का भुगतान किया गया था। प्रभावित परिवारों की संख्या के बारे में सूचना का संकलन इस मंत्रालय में नहीं किया जाता है। मध्यप्रदेश में जंगली हाथियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों को अनुग्रह राशि राहत का भुगतान प्रति मामला 10,000/- रुपए की दर से किया गया था। सम्पत्ति की क्षति के लिए मुआवजे की कोई निश्चित दर नहीं है।

(ग) सरगुजा में जंगली हाथियों को पकड़ने पर 21.37 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा, दिसम्बर, 1993 में पकड़े गए हाथियों के प्रशिक्षण पर 18.09 लाख रुपए खर्च किए गए। हाथियों को पकड़ने के बाद के वर्ष के दौरान बन्दी अवस्था में हाथियों की देखभाल पर 2.78 लाख रुपए तथा पकड़े गए हाथियों के भोजन पर 9.83 लाख रुपए खर्च किए गए।

(घ) मध्यप्रदेश में जंगली हाथियों की आवासीय आबादी नहीं है। इन हाथियों को पकड़े जाने के बाद मध्यप्रदेश से इनके आतंक की कोई और सूचना नहीं मिली है।

शिमला रेलवे स्टेशन का स्थानांतरण

*695. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शिमला रेलवे स्टेशन शहर के बस अड्डे से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जिसके फलस्वरूप शिमला शहर जाने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(ख): क्या यह सच है कि रेलवे का माल गोदाम शिमला बस अड्डे के बिल्कुल साथ है जहां रेल लाइन, शैड इत्यादि बने हुए हैं;

(ग) क्या सरकार रेलवे स्टेशन को गोदाम स्थल पर ले जाने पर विचार करेगी;

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी के. जाफ़र शरीफ़): (क) शिमला रेलवे स्टेशन और सिटी बस स्टैंड के बीच लगभग 1 कि.मी. की दूरी है। इस संबंध में शिमला जाने वाले यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होती है।

(ख) जी हां, तथापि, शिमला रेलवे स्टेशन और माल शेड के बीच केवल एक रेलपथ है तथा माल डिब्बों की सम्हलाई के लिए माल शेड क्षेत्र में दो स्कंध हैं। मौजूदा माल शेड में यात्री यातायात सम्हालने के लिए कोई अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मौजूदा स्थल जहां शिमला रेलवे स्टेशन स्थित है, सर्वथा उपयुक्त है, इसके अलावा, मौजूदा माल शेड क्षेत्र में माल तथा यात्री यातायात नहीं सम्हाला जा सकता।